भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2086

उत्तर देने की तारीख- 09/12/2024

विद्या समीक्षा केंद्र

† 2086 प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री संजय दीना पाटिल:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केन्द्र (वीएसके) स्थापित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) **इन केन्द्रों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;**

(ग) **क्या उन राज्यों में जहां वीएसके को क्रियान्वित किया गया है, वहां विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने में इसका कोई प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(घ) एकत्र किए जा रहे आंकड़ों की सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वीएसके के अंतर्गत अपनाए गए तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि स्कूल में उपस्थिति, शिक्षक के कार्य और विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों पर वास्तविक समय के आंकड़ों का सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए;

(च) विभिन्न राज्यों में वीएसके की स्थापना के लिए वर्तमान में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार की वीएसके के प्रभावी कामकाज को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और दरदराज़ के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (छ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और देश के सभी बच्चों को प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनईपी 2020 के पैरा 24.4 (ख) में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला (एनडीईएआर) की स्थापना की घोषणा करके शिक्षा के लिए देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 29 जुलाई, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में शिक्षा के लिए एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर) का शुभारंभ किया। एनडीईएआर देश के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र की एक रूपरेखा है जिसमें डिजिटल शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सिद्धांत, मानक, दिशानिर्देश और नीतियां शामिल हैं।

एनईपी के उद्देश्यों और अंतर्निहित उपायों को वृहत और लघु दोनों स्तरों पर व्यवस्थित रूप से निगरानी करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा एनडीईएआर के अनुरूप विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) शुरू किए गए हैं। चूंकि, वीएसके एनडीईएआर के ढांचे के तहत काम करते हैं, इसलिए यह व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों के साथ अंतर-संचालन और अनुकूलन सुनिश्चित करता है। इस तरह का दृष्टिकोण विभिन्न प्लेटफार्मों और संस्थाओं के बीच निर्बाध डेटा साझा करने की अनुमति देता है जिससे समन्वित प्रयासों के लिए डेटा की सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है।

वीएसके को शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई रणनीतियों के साथ तैयार किया गया है। वीएसके की एक प्रमुख विशेषता ड्रॉप आउट छात्रों की ट्रैकिंग, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी, सीखने के परिणामों की प्रगति और विभिन्न उपायों की वास्तविक समय की निगरानी है, जिसका उद्देश्य पहुँच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही को बढ़ाना है। वीएसके की समग्र संरचना अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों का मूल्यांकन, स्कूलों की मान्यता, छात्रों के लिए अनुकूली शिक्षा, विभिन्न प्रबंधन प्रकारों के तहत स्कूलों के प्रशासन की निगरानी करने में मदद करती है। वीएसके बेहतर कार्यान्वयन और परिणामों के लिए योजना के डेटा विश्लेषण में सहायता करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख शिक्षा संकेतकों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, दिनांक 9 मार्च, 2024 को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा एनसीईआरटी में राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र (आरवीएसके) का शुभारंभ किया गया।

एनसीईआरटी में राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र (आरवीएसके) को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी वीएसके के साथ जोड़ने और देश के शैक्षिक परिदृश्य का विहंगम दृश्य प्रदान करने के लिए एक संघीय वास्तुकला में विकसित किया जा रहा है। आरवीएसके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वीएसके से निकलने वाले स्कूली शिक्षा डेटा को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने और उसे त्रिकोणीय बनाने में मदद करता है, जिससे उचित स्तर पर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सीखने के परिणामों का विश्लेषण करने और उपाय या पहल की योजना बनाने और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए विभिन्न निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र प्रदान करता है। जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत मिशन जैसी कई पहलों की निगरानी वीएसके के माध्यम से की जा सकती है, जिसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करना है, और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस), राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) और आधारभूत शिक्षण अध्ययन और छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य कार्यक्रमों की निगरानी की वीएसके के माध्यम की जा सकती है। वीएसके को हाल ही में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू किया गया है और इनका उपयोग स्कूल-वार/छात्र-वार शिक्षक रिक्तियों का विश्लेषण करने, सुधारात्मक सत्रों की योजना बनाने, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आवधिक मूल्यांकन जांचों के विश्लेषण के लिए किया जा रहा है।

विभिन्न मापदंडों के संबंध में वास्तविक समय के आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टल जैसे यूडीआईएसई+ के साथ-साथ पोर्टल/एप्लिकेशन - जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, टाइम स्टैम्पिंग, जियो फेंसिंग और टैगिंग, चेहरे की पहचान जैसी सुविधाओं वाले मोबाइल एप्लिकेशन और वेब आधारित पोर्टल ऑनलाइन उपस्थिति, आवधिक मूल्यांकन जांच (पीएटी) और शिक्षा प्रबंधन के अन्य पहलुओं के लिए डेटा एकत्र करने के लिए स्कूल स्तर पर तैनात किए गए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से 108 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्रदान की थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 वीएसके पहले से ही चालू हैं। पुणे, महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था।

देश के सभी हिस्सों में विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के 'आईसीटी और डिजिटल पहल' घटक का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इन घटकों में बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। “आईसीटी प्रयोगशाला” और “स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं” के विकल्पों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के मानदंडों में आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों घटकों जैसे डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षाएं, वर्चुअल क्लासरूम, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आदि की खरीद शिक्षकों के प्रशिक्षण सहायता शामिल है। तथापि, चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर सकते हैं और अधिक डिजिटल अवसंरचना विकसित कर सकते हैं।

*****